

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	भाद्र 09, सोमवार, शाके 1942-अगस्त 31, 2020 <i>Bhadra 09, Monday, Saka 1942-August 31, 2020</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 02, 2020

जी.एस.आर.208 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 13 का संशोधन.- राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"13 चरित्र.- (1) सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या विद्यालय, जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी, के प्राचार्य/शैक्षिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाणपत्र और साथ ही ऐसे दो प्रमाणपत्र जो उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने चाहिए जो उसके विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध न हों और न उससे संबंधित हों।

(2) निम्नलिखित पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा:-

(क) नैतिक अधमता- इसमें ऐसे अपराध सम्मिलित हैं जो छल, खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण, कूटरचना, मत्तता, बलात्संग, स्त्री की लज्जा भंग, या महिला के विरुद्ध किसी अन्य अपराध, और अभ्यर्थी के बारे में जानबूझकर किसी जानकारी को छिपाना (विशिष्टतः प्रतिकूल सूचना) अर्थात् अभ्यर्थी के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत आपराधिक मामले या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी मामले या यदि किसी बोर्ड/ आयोग द्वारा अभ्यर्थी को विवर्जित किया गया है, के बारे में जानकारी को छिपाने से संबंधित हैं।

- (ख) हिंसा- इसमें हमला (भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 324, 325, 326 इत्यादि), बलवा और सांप्रदायिक सौहार्द्र विच्छिन्न करने वाले अपराध में अंतर्वलित होने (भारतीय दण्ड संहिता की धारा 146, 147, 148, 149, 153 और अध्याय 15 के अधीन अपराध, इत्यादि), गृह अतिचार (भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 452) और अति गंभीर अपराध जैसे भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 307, 308, 302 इत्यादि सम्मिलित हैं। इसमें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अध्याय 6 में यथा उल्लिखित राज्य के विरुद्ध सुनियोजित अपराध या अन्य अपराध और लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984 के अधीन हिंसात्मक प्रदर्शन और लोक संपत्ति को नष्ट करने के अपराध सम्मिलित हैं।
- (ग) अवैध व्यापार- इसमें किसी भी रीति में मानव व्यापार, आबकारी वस्तुओं या स्वापक पदार्थों का दुर्यापार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 61), या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 46) में यथा परिभाषित अवैध व्यापार, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 104) के अधीन और राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के अधीन आबकारी वस्तुओं के अनैतिक व्यापार से संबंधित अपराध सम्मिलित हैं।
- (घ) संपत्ति अपराध- सिवाय उनको छोड़कर जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 21 में उल्लिखित हैं, इसमें संपत्ति संबंधी अपराध सम्मिलित हैं।
- (ङ) विचारण या अन्वेषण के अधीन मामले- अभ्यर्थी, जिसके विरुद्ध उपर्युक्त उल्लिखित अपराधों के संबंध में कोई दाण्डिक मामला विचारण या अन्वेषण के अधीन लंबित है, पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

टिप्पण: (i) यदि विचारण के पश्चात् अभ्यर्थी सम्मानपूर्वक दोषमुक्त कर दिया जाता है, तब विभाग के स्तर पर इस प्रयोजन के लिए गठित समिति द्वारा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी पर विचार किया जा सकेगा, यदि वह भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख से तीन वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत कर देता है।

(ii) दोषमुक्ति के मामले में, विभाग को यह अधिकार होगा कि वह अभ्यर्थी के पूर्ववृत्त और उसकी उपयुक्तता पर विचार करे, लगाये गए आरोपों की कठोरता पर ऐसे विचार करते समय, विभाग यह देखेगा कि क्या प्रश्नगत दोषमुक्ति सम्मानजनक दोषमुक्ति थी या मात्र संदेह लाभ के आधार पर या समझौते पर की गयी है।

(iii) अन्वेषण के पश्चात् अभ्यर्थी के विरुद्ध मामला बंद किये जाने की दशा में, न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् अभ्यर्थिता पर विचार किया जायेगा, परंतु यह अंतिम परिणाम के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के भीतर हो और अभ्यर्थी द्वारा विभाग के ध्यान में लाया गया हो।

- (iv) बाल अपचारियों के मामले जिसमें कोई घटना अंतर्वलित है और यदि अपराध के किये जाने के समय अभ्यर्थी की आयु 16 वर्ष से कम थी, उस पर ऐसे ही विचार किया जायेगा, जैसे कि कोई बाल अपचारी 16 वर्ष की आयु से अधिक है और अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973/भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के अधीन यथा परिभाषित तुच्छ अपराध की परिभाषा में नहीं आते हैं, तो विभाग द्वारा उसे व्यस्क के समान बरता जायेगा।"

3. नियम 14 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 14 में,-

- (1) नियम 14 के विद्यमान उप-नियम (2) के विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु,-

- (i) सहरिया अभ्यर्थियों के सिवाय, किसी भी प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों की क्रमशः लम्बाई 152 सेंटीमीटर से और वजन 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होगा।
- (ii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी जिनकी लम्बाई और सीने का माप निर्धारित माप से 5 सेंटीमीटर कम है, शारीरिक रूप से उपयुक्त समझे जायेंगे, यदि नियम 14 के उप-नियम (2) में यथा अधिकथित शारीरिक उपयुक्तता मानक धारण करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं है।
- (iii) बांरा जिले के सहरिया जनजाति से संबंधित अभ्यर्थी को कांस्टेबल के पद की अपेक्षा के लिए शारीरिक रूप से उपयुक्त समझा जायेगा, यदि,-
 - (क) पुरुष अभ्यर्थी जिसकी न्यूनतम लम्बाई 160 सेन्टीमीटर से कम नहीं है और उसका बिना फुलाया हुआ सीना और फुलाया हुआ सीना क्रमशः 74 सेन्टीमीटर और 79 सेन्टीमीटर से कम नहीं है और न्यूनतम 5 सेन्टीमीटर फुलाव अपेक्षित है; और
 - (ख) महिला अभ्यर्थी जिसकी न्यूनतम लम्बाई 145 सेन्टीमीटर से कम और उसका बिना फुलाया हुआ सीना और फुलाया हुआ सीना क्रमशः 79 और 84 सेन्टीमीटर से कम नहीं है।
- (iv) गढ़वाली और गोरखा अभ्यर्थी की लम्बाई 160 सेन्टीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और उनका बिना फुलाया हुआ सीना और फुलाया हुआ सीना क्रमशः 79 सेन्टीमीटर और 84 सेन्टीमीटर से कम नहीं होना चाहिए।"; और

- (2) इस प्रकार संशोधित उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप-नियम (3) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

- "(3) **अपील-** (i) ऐसे अभ्यर्थी, जो नियत मापमान के मद्दे शारीरिक मानक परीक्षण में असफल रहे हैं, को मापमान पूर्ण होने के पश्चात् घटनास्थल पर ही तत्काल लिखित में सूचित किया जायेगा और इसी दिन बाह्य परीक्षण के लिए अपील का अधिकार होगा।
- (ii) अपील के मामलों में, तीन चिकित्सा वृत्तिकों से मिलकर बने चिकित्सा बोर्ड द्वारा उसी दिन बाह्य परीक्षण में मापमान दुबारा लिया जायेगा।
- (iii) चूंकि माप (अर्थात् सीना/वजन) अतिरिक्त समय में अभ्यर्थी के फायदे के लिए परिवर्तित हो सकता है इसलिए अपील के मामले में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा लिये गये माप अंतिम होंगे तथा किसी भी अन्य आधार पर आगे और अपील किये जाने के अध्यधीन नहीं होंगे।"

[सख्या प.2(1)कार्मिक/क-2/2003]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

संयुक्त शासन सचिव